महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में ही ईरान में जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है, उसके पश्चात् कुछ ऐसी पाबन्दी वहां लगाई गई है कि भारतीय लोग कोई खास रकम ही वहां भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं भेज सकते हैं ? ईरान ने क्या मध्य-पूर्व के देशों के साथ भी इस प्रकार की कोई बंदिश लगाई है ? यदि लगाई है, तो क्या इसका बुरा असर हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है और क्या सरकार उन देशों के प्रशासन से इस सम्बन्ध में बात करेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसका सीधा सम्बन्ध एप्रीसियेशन और डैप्रिसियेशन आफ करेन्सी से है । ईरान में क्या स्थिति हुई है, उसके सम्बन्ध में फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० रामजी सिंह : मेरे क्वैश्चन का सैकिण्ड पोर्शन है ।

'Total remittances from abroad during the last two years'

मेरा प्रश्न उससे सम्बन्धित है ।

MR. SPEAKER : Your question is whether it will be affected by the Iran revolution. He says he does not have information on that.

चौधरी बलवीर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि रूबल और रुपये का जो सम्बन्ध है, उसमें रूस वालों के रूबल की कीमत को रुपये के मुकाबले में जो बढ़ाया है तो क्या उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकार से सलाह-मशिवरा करके उसे बढ़ाया है या अपने तौर पर ही बढ़ाया है ?

MR. SPEAKER: That does not arise.

चौधरी बलवीर सिंह : यह पाउण्ड और स्टर्लिंग की है, उसके साथ ही रूबल भी है, यह भी दुनिया की करैंसी है । (व्यवधान)

SHRI GOVIND RAM MIRI: Sir, I am on a point of clarification. I want to draw your kind attention to the list of questions printed by the Lok Sabha Secretariat. Kindly see Qn. No. 812. In the English version the answer has been put in the name of the Deputy Prime Minister and Finance Minister....

MR. SPEAKER: When the Member is not here, why do you take objection to something?

SHRI GOVIND RAM MIRI: In the Hindi version it is put in the name of the Minister of Comerce, Civil Supplies and Cooperation.

MR. SPEAKER: When the questioner is not here, that question does not arise.

It may be a mistake. In one day we get over 900 questions : you must also remember that. There are days when we get even a thousand questions. All these have to be vetted by the Office. We are trying our best to do it.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Is that an excuse for committing a mistake.

MR. SPEAKER: Human errors are always possible.

Cadre Management Plans for Officers of Income Tax Department

+

*†814. SHRI RAGHAVJI :

DR. VASANT KUMAR PANDIT:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that Government had prepared a Cadre Management Plan from 1st April, 1975 to 31st March, 1979 for Class-I Officers of the Income-tax Department which has resulted in large number of promotions to higher ranks;

(b) whether it is also a fact that second Cadre Management Plan for Class-I Officers is also being prepared by the Income-tax Department to give more incentives of promotions to higher ranks;

(c) whether it is also a fact that no Cadre Management Plan for Class-III Officers has been prepared by the Income-tax Department and the reasons therefor;

(d) whether on principles and priorities the Cadre Management Plans should first start from bottom and not from top levels; and

(e) if so, whether the Government are going to take and complete the Cadre Management Plan for Class-III Officers and suspend one for Class-I Officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULIAH) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In pursuance of the Government Policy, a Cadre Management Plan for Indian Revenue Service (Income-Tax) Group-A, was for the first time prepared for the period 1st April, 1975 to 31st March, 1979. It resulted in creation of 80 posts of Commissioners and 87 posts of Assistant Commissioners, by upgradation, and 100 leave reserve posts of Income-tax Officers (Group-A) Junior Scale, and introduction of selection grade for 99 Assistant Commissioners (Rs. 2000—2200).

(b) Cadre Management Plan for the period 1-4-1979 to 31-3-1982 is now being prepared, as the first Cadre Management Plan expired on 31-3-1979. All Central Group-A Services are required to undertake cadre reviews and prepare Cadre Management Plans after every three years. The basic objective of preparing these Plans is to review the cadre structure and not necessarily to provide further avenues for promotion.

(c) The concept of Cadre Management Plan stemmed from the recommendations of the Administrative Reforms Commission with reference to the All India and Central Services. As such, the question of Cadre Management Plan, being drawn up for Class-III officials, did not arise. Moreover, it is not possible to draw up Cadre Management Plan for Class-III officials in the Income-tax Department for the reason that the Controlling and Appointing authorities for Class-III officials, being the Commissioners of Income-tax, any scientific cadre review is not possible on All India basis. It is a huge task to undertake such reviews for the charge of each Commissioner. Class-III cadres in Income-tax Department comprise of numerous grades, such as, Supervisors, Head Clerks, Inspectors, Tax Assistants, Stenographers, UDCs, LDCs, Notice Servers, etc. To undertake a review of all these cadres scattered over all the Commissioners' Charges in the country is not feasible. The problems of the various cadres in Class-III are also different.

(d) and (e). Does not arise in view of (c) above.

श्री राघवजी : अध्यक्ष महोदय विडम्बना यह है कि हमारे मैनेजमेंट प्लान जो बनते हैं वह प्रथम श्रेणी के अधिकारी बनाते हैं । जब वह मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो वास्तव में उनका दायित्व यह है कि नीचे के कैडर से लेकर ऊपर के कैडर तक सब के लिये पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिये । प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के हितों की तो रक्षा होती है, परन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की जाती है । प्रश्न के उत्तर में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि कमिश्नर की पोस्टें और एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट बढ़ाई गई हैं, सलैक्शन ग्रेड भी बढ़ाये गये हैं लेकिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कोई भी पोस्ट बढ़ाने या प्रोमोशन का उसमें जिक्र नहीं किया गया है ।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो जानकारी इस उत्तर में दी गई है कि 80 पोस्टें कमिश्नर की की गई हैं, वास्तव में वह 86 हैं। 87 पोस्टें जहां पर इन्होंने कहा है कि एसस्टिंट कमिश्नर की गई हैं वह वास्तव में 117 हैं। यह राज्य-सभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। इनकम टैक्स आफिसर की 100 पोस्टें बताई हैं वास्तव में वह 250 हैं। यह सब राज्य सभा के प्रश्न के उत्तर में दिया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्लास-1 के अधिकारियों की पोस्टों को बढ़ाने के लिये तो कानून में भी संशोधन कर दिया जाता है, लेकिन तृतीय श्रेणी की पोस्टों के बारे में, जबकि हर जगह कमिश्नर मांग कर रहे हैं कि इन्सपेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि इन्सपेक्टरों का सलैक्शन हो चुका है, कई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको दस साल के बाद भी प्रोमोशन नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कैडर मैनेजमेंट प्लान लागू करेगी और जितनी जगहों की मांग है, उनको जल्दी से जल्दी भरेगी।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं मेम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि कैडर मैनेजमेंट प्लान महज स्टाफ को प्रोमोशन देने के लिए नहीं बनता है। (व्यवधान) अगले तीन सालों में कितना काम बढ़ेगा, कितनी पोस्ट्स बढ़ानी चाहिए, पिछले तजर्बे की बिना पर जहां जहां इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वगैरह बातों पर गौर करने के लिए कैडर के स्ट्रक्चर का रीव्यू किया जाता है। लेकिन उनके साथ साथ अगर जगह होती है, तो प्रोमोशन भी होता है।

जहां तक क्लास थ्री कैडर का सवाल है, वह इतना अनमैनेजेबल है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में जो सौ डी सौ कमिश्नरर्ज हैं, वे उसको कंट्रोल करते हैं। हर कमिश्नर अलाहिदा अलाहिदा अपना कैडर मैनेजमेंट प्लान बना सकता है। कोई आलइंडिया मैनेजमेंट प्लान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रोमोशन के सिलसिले में कोई स्टैगनेशन होता है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले साल में चार हजार से ज्यादा इनकम टैक्स एसिस्टेंट्स की पोस्ट्स क्रीएट की गई - इस लिए भी कि काम बढ़ा है और कुछ इस लिए भी कि यू डी सीज में स्टैगनेशन था। इस तरह चार हजार से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स एसिस्टेंट्स की जगह पर प्रोमोशन मिली। इसके अलावा 500 पोस्ट इन्स्पैक्टर्ज की नई अभी हाल में क्रीएट की गई।

श्री राघवजी : वे भरी नहीं गई हैं।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : गवर्नमेंट ने उसकी मन्जूरी दी है। उनको भरने का इन्तजाम जल्दी ही रहा है।

स्टेनोग्राफरर्ज के लिए सिलेक्शन ग्रेड मौजूद है। दूसरे लोग हायर ग्रेड्ज में चले जाते हैं। एल डी सीज को यू डी सी की पोस्टस पर जाने का बराबर मौका मिलता है। ये सारी पोस्टस अधिकतर प्रोमोशन से भरी जाती हैं। कैडर मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट आफ इंडिया में डायरेक्टली रेक्रूटिड सर्विसिज के लिए बनता है।

श्री राघवजी : मंत्री महोदय ने कहा है कि तृतीय श्रेणी में सिलेक्शन ग्रेड है। लेकिन तृतीय श्रेणी में सिलेक्शन ग्रेड नहीं है। न इन्स्पेक्टर्ज में और न क्लास टू इनकम टैक्स आफिसर्ज के लिए सिलेक्शन ग्रेड है। एसिस्टेंट कमिश्नर्ज के लिए सिलेक्शन ग्रेड बना दिया गया है, जिसका वेटिंग पीरियड दस साल का है, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्म-

चारियों—इन्सपैक्टर्स वगैरह - को 15 साल से कोई प्रोमोशन नहीं मिला है। हर एक कमिश्नर इनकम टैक्स इन्सपैक्टर्स की पोस्ट्स मांग रहा है। लेकिन उन पोस्ट्स पर नियुक्ति नहीं हो रही है।

उत्तर में बताया गया है कि 35.000 कर्मचारी इनकम टैक्स आफिस में काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति कमिश्नर्स द्वारा होती है, इसलिए उनके लिए मैनेजमेंट प्लान नहीं बन सकता है। अभी तीन दिन पहले रेलवे मंत्री ने घोषणा की है कि वह रेलवेज़ में मैनेजमेंट प्लान लागू कर रहे हैं, जहां 25 लाख लोग काम करते हैं। लेकिन मंत्री महोदय 35,000 कर्मचारियों के लिए मैनेजमेंट प्लान लागू नहीं कर रहे हैं। चूंकि अब समरी एसैसमेंट की स्कीम लागू हो गई है, इस लिए अब इनकम टैक्स आफिसर्ज और ऊपर के कैडर्ज की जरूरत कम हो गई है और इन्सपैक्टर्ज के कैडर की जरूरत अधिक हो गई है। इस लिए क्या सरकार कमिश्नर्ज से पता लगायेगी कि इन्स्पैक्टर्ज - तृतीय श्रेणी - की कितनी जगहों की जरूरत है और क्या वह उन जगहों को शीघ्र से शीघ्र भरने का निर्देश देगी ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं मेम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमेशा कमिश्नर्ज से रीव्यू कराती रहती है कि कितनी पोस्ट्स की जरूरत है और कहां कहां बढ़ानी चाहिए, और वह होता भी है। अगर उन के लिए कोई कैडर मैनेजमेंट प्लान बने, तो वह कमिश्नर-वाइज ही हो सकता है। मेम्बर साहब के सजेस्शन पर गवर्नमेंट जरूर गौर करेगी कि क्या यह मुमकिन हो सकता है।

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Sir, under the guise of Administrative Reforms Commission, the new management cadre was brought in force. There were almost 400 Class-I posts which had been created. To fit in these Class-1 posts, even some lower cadre posts were upgraded.

For class III, there is no question at all of their promotion. They have to wait at least for 16-20 years. By the new cadre management plan, the period of ten years for Class I has now been reduced to 5 years. So, my suggestion to the Government is that any plan for cadre management should begin from below. The planning should be from below and not from the top. Therefore, will the Government put into operation some of the suggestions of the Administrative Reforms Commission pertaining to Class III so that their future may become bright and some chances for promotion may be given to them?

SHRI ZULFIQUARULLAH: I have already replied to this point, but again I can assure the hon. Member that his suggestion will receive due consideration.

Transfer of Pay and Accounts Office at Mathura to Nasik Road

*815. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Pay and Accounts Office (Defence) at Mathura is being transferred to Nasik Road despite the representations made by the employees against this proposal;

(b) whether any understanding was given to the employees that certain other allied offices will be shifted instead to Mahura; and

(c) if so, how is it going to be implemented and when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) The Pay Accounts Offices and the Record Offices are functionally interdependent on each other's records. Consequent on the move of the Record Office to Nasik Road Camp, the Pay Accounts Office is being shifted in phases in public interest. The first